बुधवार, 11 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

दक्षिणेश्वर सुरेश बने भारत के नए नायक,गुमनामी से स्टारडम तक का सफर

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

सलमान खान और संजय दत्त ने किया ट्रेलर में तहलका

Page-05

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की पहल,

विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा

- **विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिस पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा है।**
- **विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही में स्पीकर ने निष्पक्षता नहीं बरती, जबकि सत्तापक्ष ने इन आरोपों को**

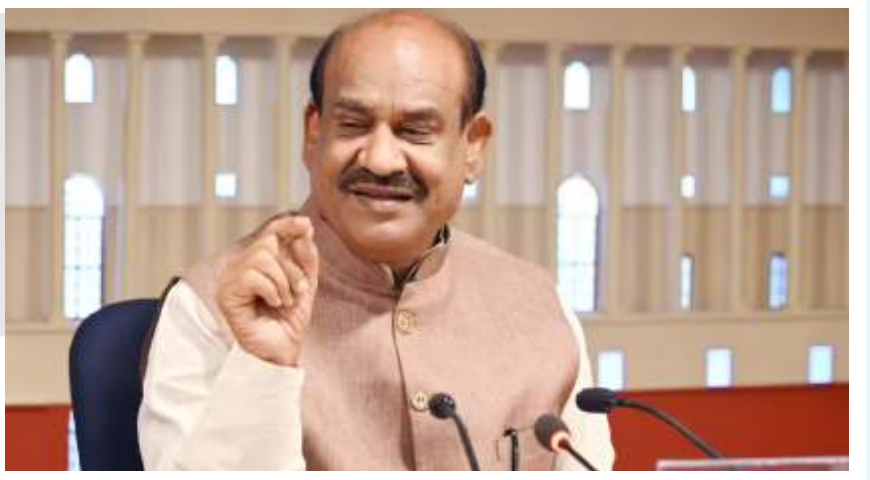

नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में विपक्ष की ओर से लोकसभा सचिवालय को एक औपचारिक नोटिस सौंपा गया है, जिस पर 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। यह कदम संसद के मौजूदा सत्र के दौरान उठाया गया है और इसे विपक्ष द्वारा सरकार पर बढ़ते हमलों के रूप में देखा जा रहा है।विपक्षी दलों का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को प्राथमिकता मिली। विपक्ष का यह भी कहना है कि सदन में बार-बार स्थगन, विपक्षी सांसदों के माइक बंद किए जाने और प्रश्नकाल को प्रभावित करने जैसी घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं।सूत्रों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमामय और निष्पक्षता का प्रतीक होता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह भावना कमजोर हुई है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर को सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष के हित में निर्णय लेने चाहिए।इस कदम पर सत्तारूढ़ दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष के आरोपों को निराधार और राजनीतिक स्टंट करार दिया है। सत्तापक्ष का कहना है कि स्पीकर ओम बिरला ने हमेशा संविधान, संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुसार ही सदन का संचालन किया है। उनका यह भी आरोप है कि विपक्ष सदन को सुचारु रूप से चलने नहीं देना चाहता और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास इससे कहीं अधिक सांसदों का समर्थन है। अब यह निर्णय लोकसभा सचिवालय को लेना है कि नोटिस को स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है, तो प्रस्ताव को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम हो, लेकिन यह विपक्ष की एकजुटता और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज़ होने की संभावना है।

PM मोदी की डिग्री विवाद पर DU सख्त, हाईकोर्ट में कहा- याचिका केवल प्रचार के लिए

नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना स्पष्ट रुख रखते हुए कहा है कि यह याचिका केवल सनसनी फैलाने और बेवजह विवाद खड़ा करने का प्रयास है। विश्वविद्यालय ने अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही आवश्यक जानकारियां दी जा चुकी हैं और बार-बार सवाल उठाना दुर्भावनापूर्ण है।यह मामला प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दायर याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता का कहना है कि डिग्री से जुड़े दस्तावेजों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय का तर्क है कि विश्वविद्यालय ने नियमों और कानून के तहत पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।

देशभर में विरोध के बाद झुके मेकर्स,

हाईकोर्ट में टाइटल बदलने का भरोसा

नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

अभिनेता मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'घूसखोर पंडित' को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध और हंगामे के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। विवाद बढ़ने पर फिल्म के निर्माताओं ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वे फिल्म का शीर्षक बदलने के लिए तैयार हैं।बताया जा रहा है कि फिल्म के नाम को लेकर एक विशेष समुदाय की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया था। इसके चलते कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म का टाइटल आपत्तिजनक है और समाज के एक वर्ग को

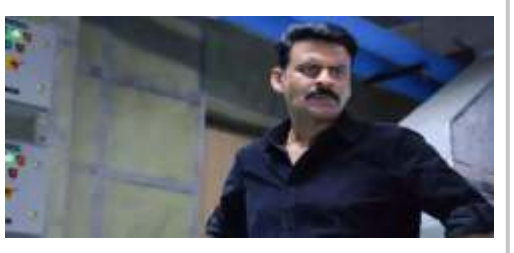

नकारात्मक रूप में दर्शाता है।मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनका किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। विवाद को शांत करने और सौहार्द बनाए रखने के लिए मेकर्स फिल्म का नाम बदलने पर सहमत हो गए हैं।

तेज प्रताप यादव ने दिखाई दरियादिली,

अभिनेता राजपाल यादव को दी 11 लाख रुपये की आर्थिक मदद

पटना,टीवी भारतवर्ष

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आकर 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस पहल की सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सराहना की जा रही है।जानकारी के मुताबिक, अभिनेता राजपाल यादव हाल के दिनों में एक निजी आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव ने मानवीय आधार पर उनकी सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय एक-दूसरे की मदद करना ही समाज की

यह मदद किसी राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं, बल्कि एक इंसानी फर्ज के तौर पर की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजपाल यादव जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे|

असम की राजनीति में तकरार तेज,

हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई पर दायर किया 500 करोड़ का मानहानि केस

गुवाहाटी, टीवी भारतवर्ष

असम की राजनीति में सियासी घमासान और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि (डिफेमेशन) का मुकदमा दायर किया है। यह मामला दोनों नेताओं के बीच लगातार चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बाद सामने आया है।मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का आरोप है कि गौरव गोगोई ने उनके खिलाफ सार्वजनिक मंचों और बयानों में ऐसे आरोप लगाए हैं, जो न केवल तथ्यहीन हैं बल्कि उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सीएम का कहना है कि इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया।सूत्रों के अनुसार, मानहानि का यह मामला एक सिविल केस के तौर पर दायर किया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि वे राजनीति में आलोचना से नहीं डरते, लेकिन झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा है कि वे सरकार से जुड़े मुद्दों और कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते रहेंगे और कानूनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री के कदम को असहमति की आवाज़ को दबाने वाला बताया है। इस घटनाक्रम के बाद असम की राजनीति और ज्यादा गरमा गई है। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में राज्य की राजनीति को और अधिक प्रभावित कर सकता है।फिलहाल, सभी की निगाहें अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखना अहम होगा कि यह कानूनी लड़ाई किस दिशा में जाती है और इसका असम की सियासत पर क्या असर पड़ता है। इस घटनाक्रम के बीच राज्य में राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज़ हो गई है, जिससे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले चुनावी माहौल में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।

भारत-यूएस ट्रेड डील पर रूस का बयान,

विदेश मंत्री लावरोव बोले- अमेरिका सस्ता तेल खरीदने से रोक रहा है

भारत के लिए यह पल कसौटी का है। एक तरफ पश्चिमी दबाव, दूसरी तरफ सस्ती आपूर्ति से मिलने वाली राहत। भारत के लिए महंगा ईंधन सीधे महंगाई, उद्योग लागत और आम जन के जीवन पर असर डालता है। इसलिए ऊर्जा फैसले भावनाओं से नहीं, कठोर गणना से होंगे। यही परिपक्व विदेश नीति का संकेत भी है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका से भारत की ट्रेड डील के बाद रूस सरकार की ओर से किसी बड़े मंत्री की यह पहली आधिकारिक टिप्पणी मानी जा रही है, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलकर कहा है कि वाशिंगटन भारत सहित कई देशों को सस्ते रूसी तेल की खरीद से रोकने की कोशिश कर रहा है। एक टीवी साक्षात्कार में लावरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका प्रतिबंध, टैरिफ और तरह तरह के रोक लगाने वाले कदमों के जरिये देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूसी ऊर्जा से दूर हो जाएं और महंगी अमेरिकी आपूर्ति लें। लावरोव ने कहा कि यह केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति है जिसका लक्ष्य वैश्विक आर्थिक दबदबा बनाना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मसले पर बातचीत के दौरान रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव को महत्व दिया था और आगे व्यापक सहयोग की उम्मीद रखी थी, लेकिन हालात उलट दिशा में जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और खुले समुद्र में टैंकरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं जो समुद्री कानून की भावना के खिलाफ हैं। रूसी मंत्री ने कहा कि यूरोप को पहले ही रूसी ऊर्जा से दूर किया जा चुका है और अब भारत तथा अन्य भागीदार देशों को भी सस्ती आपूर्ति से काटने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका चाहता है कि देश महंगी अमेरिकी एलएनजी और अन्य ऊर्जा स्रोत खरीदें, भले ही वह उनके आर्थिक हित के खिलाफ हो। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों की तरह सभी के साथ सहयोग के लिए खुला है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि लेकिन खुद अमेरिकी नीतियां रास्ते में कृत्रिम रुकावटें खड़ी कर रही हैं। हम आपको यह भी बता दें कि रूसी तेल पर भारत ने अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति केवल राष्ट्रीय हित से संचालित होगी। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता पर्याप्त उपलब्धता, उचित कीमत और भरोसेमंद आपूर्ति है। भारत ने यह साफ किया कि वह बाजार की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखकर स्रोतों का विविधीकरण करेगा। दरअसल, अमेरिका की ओर से भारत पर लगाये गये अतिरिक्त टैरिफ हटाने के फैसले के बाद यह अटकलें तेज हुईं कि क्या भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद घटाएगा? हालांकि नई दिल्ली ने न तो खरीद रोकने की पुष्टि की है और न ही इन खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी फैसले इसी कसौटी पर होंगे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का आरोप है कि रियायती रूसी तेल की खरीद से मास्को को यूक्रेन युद्ध के लिए संसाधन मिलते हैं। इस पर भारत का रुख रहा है कि वह अपने उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगा। देखा जाये तो ऊर्जा आज की दुनिया में सामरिक शक्ति का मूल आधार है। जो देश तेल और गैस की धार को मोड़ सकता है, वह कई बार गोलियों के बिना भी दबाव बना सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका सचमुच बाजार के नाम पर दबाव की राजनीति कर रहा है तो यह मुक्त व्यापार के दावे पर खुद सवाल खड़ा करता है। सामरिक नजर से देखें तो रूसी तेल ने भारत को छूट दी है कि वह अपनी रिफाइनरी क्षमता का पूरा उपयोग करे और निर्यात भी बढ़ाए। इससे विदेशी मुद्रा आय और कूटनीतिक लचीलापन दोनों मिले हैं।

DRDO में ट्रेनिंग का अवसर: हर महीने हजारों रुपये, जानें आवेदन प्रक्रिया

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए यह खबर बेहद काम की है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। दरअसल, रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के ISSA ने एक वर्षीय प्रशिक्षण के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक व योग्य स्नातक और डिप्लोमा धारक ईमेल के जरिए स्कैन किए हुए आवेदन भेजकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि, आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2026 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उम्मीदवार कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech में प्रथम श्रेणी की डिग्री अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित में M.Sc में प्रथम श्रेणी की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ वे उम्मीदवार पत्र है, जिन्होंने वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 या 2025 में अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण की हैं, ले उम्मीदवार जो पहले से ही अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत Apprentice कर चुके हैं या वर्तमान कर रहे हैं या फिर जिनके पास 1 साल का वर्क अनुभव है, वे लोग ही इसके लिए पात्र नहीं हैं।

ब्रिटेन: शबाना महमूद बन सकती हैं देश की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री

शरद पवार की तबियत पर पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने जताई चिंता

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार को फोन किया, जिन्हें सोमवार को सीने में संक्रमण के बाद पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री ने 85 वर्षीय पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पवार से फोन पर बात की। एनसीपी नेता को खांसी और गले में संक्रमण की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स शुरू किया है, जो अगले चार दिनों तक चलेगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए पवार को आराम करने और फिलहाल किसी से न मिलने की सख्त सलाह दी गई है। अस्पताल में उनके कई मेडिकल टेस्ट हुए और फिलहाल उनका इलाज जनरल वार्ड में चल रहा है। रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ और प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज़ ग्रांट ने बताया कि शरद पवार का सीटी (कंप्यूटेड टोमोग्राफी) स्कैन किया गया, जिसमें उनके सीने में संक्रमण पाया गया। इलाज कर रहे डॉक्टरों में से एक डॉ. अभिजीत लोढ़ा ने कहा कि शारीरिक परिश्रम के कारण उन्हें खांसी और सीने में जकड़न हो गई। कई टेस्ट किए गए हैं और फिलहाल इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर है। सभी टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद इलाज में कोई भी बदलाव तय किया जाएगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल समेत उनके सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं। उन्हें सामान्य कमरे में रखा गया है और वे आईसीयू में नहीं हैं।

भारत के बाद अमेरिका-बांग्लादेश के बीच बड़ा व्यापार समझौता, टैरिफ घटकर 19% हुआ

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत, बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ (Reciprocal Tariff) को घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, अमेरिका ने उन परिधानों (Garments) को 'ड्यूटी-फ्री' (शून्य शुल्क) प्रवेश देने का वादा किया है, जिनमें अमेरिकी कच्चे माल का उपयोग किया गया होगा। यूनुस ने X पर लिखा, "वॉशिंगटन ने US मटीरियल से बने कुछ खास बांग्लादेशी कपड़ों के लिए ज़ीरो टैरिफ एक्सेस पाने का रास्ता बनाने का वादा किया है।" मौजूदा टैरिफ राहत वॉशिंगटन के साथ नौ महीने से ज़्यादा समय तक चली बातचीत के बाद मिली है। US ने शुरू में अप्रैल में बांग्लादेशी एक्सपोर्ट पर 37 परसेंट तक टैरिफ का प्रस्ताव रखा था। गहरी बातचीत के बाद, ढाका ने पिछले साल अगस्त में कटौती पक्की कर ली, जिससे रेट 20 परसेंट तक आ गया। यूनुस ने इस एग्रीमेंट को नौकरियों की सुरक्षा और ग्लोबल टेक्सटाइल सप्लाई चेन में बांग्लादेश की स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ढाका के जारी एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, बांग्लादेश की तरफ से कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीर उद्दीन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान ने और US की तरफ से US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर जैमीसन ग्रीर ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए। ग्रीर ने एग्रीमेंट को पूरा करने की कोशिशों के लिए यूनुस और बातचीत करने वाली टीम की तारीफ की। बयान में कहा गया है, "यह एग्रीमेंट US ट्रेड पॉलिसी में बांग्लादेश की स्थिति को मजबूत करेगा।" व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया कि दोनों देश बांग्लादेश में नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए भी कमिटेड हैं। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की इकॉनमी की रीढ़ है, जो कुल एक्सपोर्ट कमाई का 80 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा है। इसमें लगभग चार मिलियन वर्कर काम करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ग्रामीण और कम इनकम वाले बैकग्राउंड की महिलाएं हैं, और यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 10 परसेंट का योगदान देता है। इंडस्ट्री लीडर्स ने कहा कि कम टैरिफ रेट से बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को U S मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद मिल सकती है, जो उनके सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में से एक है।

छत्तीसगढ़: सुकमा में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़, 65 बीजीएल सेल बरामद

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को एक विशेष अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के एक गुप्त ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर वहां से 65 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल बरामद किये गए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद रायगुडेम गांव के पास के पहाड़ी जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और स्थानीय पुलिस की एक टीम ने यह अभियान चलाया। पुलिस अधिकारी ने कहा, '' हमने 65 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) सेल और कमर पर बांधे जाने वाली दो थैली बरामद कीं। अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में बीजीएल सेल की बरामदगी से नक्सलियों की किसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षाबलों ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और आस-पास के जंगलों में नक्सलियों की तलाश जारी है। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुरक्षाबलों को एक ऐतिहासिक रणनीतिक सफलता मिली है। सुकमा और बीजापुर जिलों में कुल 51 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 1.61 करोड़ का इनाम घोषित था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की समय-सीमा (Deadline) तय की है। इस सामूहिक आत्मसमर्पण से ठीक एक दिन पहले, सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ के जंगलों में एक बड़ी मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली नेता एल. प्रभाकर राव को छह अन्य नक्सलियों के साथ ढेर कर दिया था। प्रभाकर राव एक खतरनाक 'एंबुश रणनीतिकार' माना जाता था। उसकी मौत ने नक्सलियों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया है।

संपादक की कलम से

भारत सरकार द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियमों की घोषणा एक साहसिक और आवश्यक कदम के रूप में देखा जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग ने सूचना की विश्वसनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा को चुनौती दी है। इसी को देखते हुए सरकार ने तीन घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने और एआई-निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाने को अनिवार्य किया है। यह न केवल उपयोगकर्ताओं को सचेत करता है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करता है।आज के डिजिटल युग में सूचना की रफ्तार इतनी तेज है कि झूठी या भ्रामक सामग्री केवल कुछ मिनटों में फैल सकती है। डीपफेक और एआई-निर्मित वीडियो या चित्र विशेष रूप से खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता का भ्रम पैदा कर सकते हैं और सामाजिक या राजनीतिक तनाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम प्लेटफॉर्म्स और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए चेतावनी का काम करता है।हालांकि, नियमों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी। प्लेटफॉर्म्स को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा, बल्कि हर सामग्री का मूल्यांकन करने और सही लेबल लगाने की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, उपयोगकर्ताओं की डिजिटल स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा।फिर भी, यह कदम डिजिटल दुनिया में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जब एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक तेजी से समाज के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो उसके उपयोग के नियम और पारदर्शिता की स्पष्टता अनिवार्य हो जाती है। सरकार की यह पहल एक संदेश देती है कि तकनीक की शक्ति तभी उपयोगी है जब उसका उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। कहा जा सकता है कि एआई और डिजिटल मीडिया के भविष्य में नियमों और पारदर्शिता का यह नया ढांचा न केवल सामाजिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और उपयोगकर्ताओं के लिए जवाबदेही का भी नया मानक स्थापित करेगा। यह समय की मांग है कि हम तकनीक की शक्ति को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसका जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करें।

राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का समर्थन किया,

कहा– मुझे सेना प्रमुख पर भरोसा है, प्रकाशक पर नहीं

पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर विवाद तेज हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रकाशक पेंगुइन पर भरोसा नहीं करते और नरवणे पर विश्वास रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, किताब की 'अप्रकाशित' प्रतियों के लीक होने की जांच जारी है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर जारी विवाद और तेज हो गया है। इस विवाद में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी सीधे हस्तक्षेप कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किताब के प्रकाशक 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' के बजाय पूर्व सेना प्रमुख की बातों पर भरोसा करते हैं।कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस विवाद में या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। उन्होंने मंगलवार को संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, "मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन किताब Amazon पर उपलब्ध है। इस कारण मुझे पेंगुइन से ज़्यादा नरवणे जी पर भरोसा है।"राहुल गांधी ने नरवणे के 2023 के एक ट्वीट का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने अपनी नई किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को प्रमोट किया था। उन्होंने कहा कि किताब में दिए गए कुछ बयान भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, "यहां मिस्टर नरवणे का एक ट्वीट है, जिसमें लिखा है कि बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें। मुझे लगता है कि उनकी किताब में कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है।"इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने दावा किया कि पुस्तक अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित या वितरित नहीं की गई है और इसके डिजिटल संस्करण का प्रसार गैरकानूनी है। हालांकि, किताब अमेज़न जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि प्रकाशक और किताब के बीच क्या स्थिति है। राहुल गांधी का कहना है कि किताब के अंश और इसकी उपलब्धता इस बात को साबित करते हैं कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही है।राहुल गांधी ने आगे कहा कि किताब में लद्दाख गतिरोध और अग्निपथ योजना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नरवणे के स्वतंत्र विचार शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी किताब या प्रकाशन को लेकर जनता और सरकार को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उनके अनुसार, यह मामला केवल पुस्तक का विवाद नहीं है, बल्कि स्वतंत्र राय और सूचना के अधिकार से जुड़ा मामला भी है।कांग्रेस नेता ने पेंगुइन और नरवणे दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि "या तो मिस्टर नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। इसलिए इस मामले में मेरा भरोसा नरवणे पर है।" उनके इस बयान से साफ़ हो गया है कि उन्होंने इस विवाद में नरवणे का पक्ष लिया है और प्रकाशक पर संदेह जताया है।वहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। जांच चल रही है कि किताब की 'अप्रकाशित' प्रतियां लीक कैसे हुईं। यह मामला अब प्रशासन और मीडिया दोनों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि डिजिटल संस्करण किस तरह से जनता के बीच आया और इसका कानूनी पक्ष क्या है।इस विवाद ने भारत के प्रकाशन क्षेत्र, सेना और राजनीति के बीच जटिल स्थिति पैदा कर दी है। किताब के प्रकाशन को लेकर विवाद और तेज़ होने के कारण कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या किसी पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण को रोकना उचित है, या क्या यह मामला केवल प्रकाशन और वितरण की प्रक्रिया तक सीमित है। राहुल गांधी के बयान ने इस विवाद को और सार्वजनिक कर दिया है, जिससे यह न केवल संसद में, बल्कि मीडिया और जनता में भी चर्चा का विषय बन गया है।'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किताबें और उनके लेखक केवल साहित्यिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी इंगित किया कि जनता को पता होना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है और किसके दावों पर भरोसा किया जाए। उनके अनुसार, यह मामला केवल किताब का विवाद नहीं है, बल्कि सत्य, स्वतंत्रता और विश्वास का मामला भी है।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस विवाद का क्या समाधान होगा और किताब के प्रकाशन को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने राजनीति और सेना के बीच आम चर्चा को नई दिशा दी है। जनता, मीडिया और विशेषज्ञ अब इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि किताब के अंश और प्रकाशक के दावे के बीच असली सच क्या है।इस विवाद ने यह भी दिखाया है कि किसी पूर्व सेना प्रमुख की किताब, उसके विचार और बयान केवल साहित्यिक मूल्य तक सीमित नहीं होते। वे राष्ट्रीय सुरक्षा, नीतिगत फैसलों और राजनीतिक विमर्श से भी सीधे जुड़े होते हैं। राहुल गांधी के समर्थन से यह मामला और सार्वजनिक और विवादास्पद हो गया है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।

रेवंत रेड्डी का BJP पर तंज:

पार्टी राम का नाम लेती है, वोट AIMIM के सहारे मांगती है

टीवी भारतवर्ष तेलंगाना

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाजपा भगवान राम का नाम तो लेती है, लेकिन असल में उनके लिए सबसे बड़ा सहारा और इकलौता भगवान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। रेवंत रेड्डी ने सोमवार को हैदराबाद में प्रेस कॉफ्रेंस कर कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बार-बार ओवैसी को मुद्दा बनाती है। अगर भाजपा के राजनीतिक इतिहास और बयानों का विश्लेषण करें, तो उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान असदुद्दीन ओवैसी हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकतंत्र में AIMIM भी एक राजनीतिक दल है। वह चुनाव लड़ती है और जहां जनसमर्थन मिलता है, वहां जीतती है। उन्होंने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में AIMIM ने चुनाव लड़े और पश्चिम बंगाल में पांच सीटें भी जीतीं। ऐसे में उन्हें भूत-प्रेत या राक्षस बताकर वोट मांगना वैचारिक गरीबी है। रेवंत रेड्डी ने अंत में तेलंगाना की जनता से सवाल करते हुए कहा कि सिर्फ धार्मिक नफरत भड़काकर, कुछ नेताओं को राक्षस बताकर राजनीति में जिंदा रहना वैचारिक गरीबी है। इस वैचारिक गरीबी को देखकर तेलंगाना की जनता को तय करना चाहिए कि भाजपा को वोट देना है या नहीं। भाजपा हर बार असदुद्दीन ओवैसी को खलनायक के रूप में पेश करती है। जब केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो अगर ओवैसी इतने बड़े विलेन हैं, उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। हर चुनाव में भाजपा ओवैसी को "अलादीन के चिराग" की तरह सामने रखकर वोट मांगती है। ओवैसी का नाम लेकर बार-बार चुनावी समर्थन मांगा जाता है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और किसी राजनीतिक दल या उसके नेताओं को नकारात्मक रूप में पेश कर राजनीति करना सही नहीं है। ये विचारधारात्मक कमजोरी है।

नरवणे की किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पर प्रकाशक का बयान: अब तक नहीं हुई प्रकाशित

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बहुचर्चित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' एक बार फिर विवाद और चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। इस पुस्तक को लेकर प्रकाशक संस्थान 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' (PRHI) ने स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक के प्रकाशन और वितरण के विशेष अधिकार केवल उनके पास हैं और यह पुस्तक अभी तक आधिकारिक रूप से बाजार में नहीं आई है।इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। इस मामले ने मीडिया और राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बन गया है। इसको देखते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि पुस्तक की मुद्रित या डिजिटल किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं की गई है।प्रकाशक ने स्पष्ट किया, "पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह बताना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है।"बयान में आगे कहा गया कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति मुद्रित या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में जो पुस्तक के संस्करण प्रसारित हो रहे हैं, उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा।इस बीच, पिछले सप्ताह संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर इस पुस्तक की एक प्रति दिखाते हुए देखा गया था। इस घटना के बाद पुस्तक और उसके प्रकाशन को लेकर राजनीतिक और मीडिया में बहस और विवाद और तेज़ हो गया है। प्रकाशक ने दोहराया कि अभी तक कोई भी आधिकारिक संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया है और जो संस्करण सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, वे अवैध हैं।यह विवाद इस बात को भी उजागर करता है कि किसी पूर्व सेना प्रमुख की किताब केवल साहित्यिक महत्व नहीं रखती, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक और संवेदनशील मामलों पर भी बहस हो सकती है।

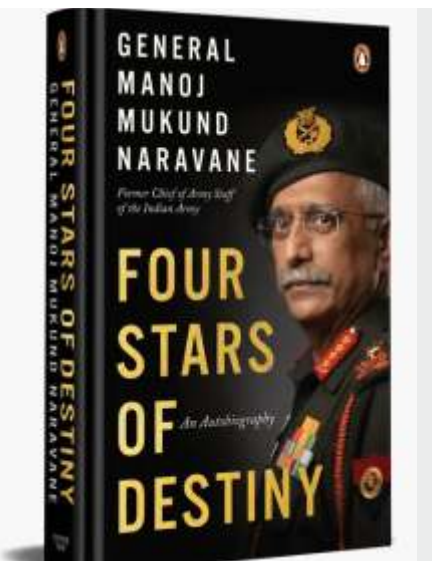

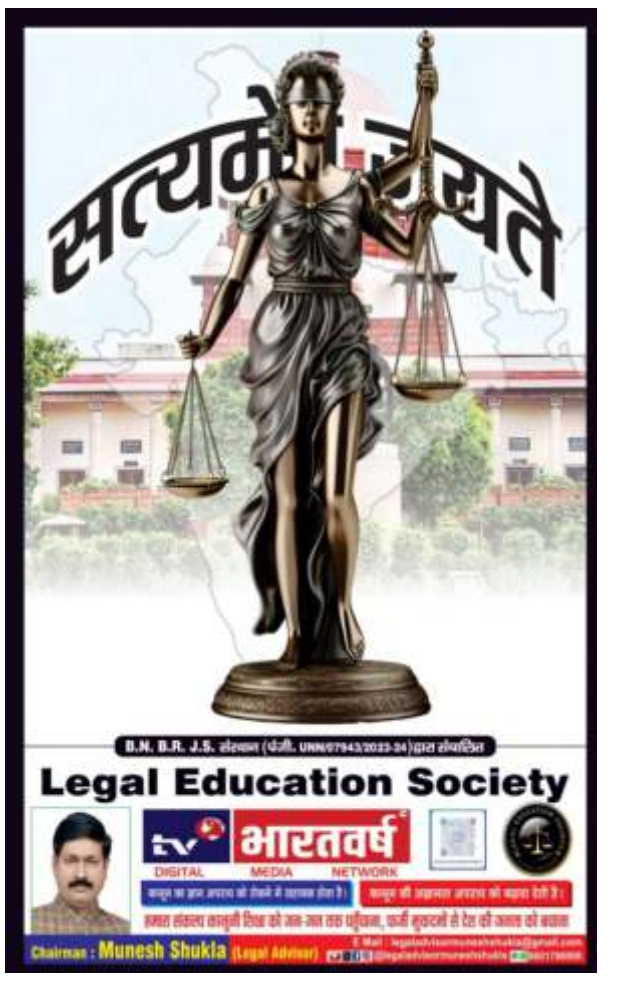

दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल था गैस-लैंप से संचालित

अगर आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए रोजाना गाड़ी से सफर करते हैं, तो आप यह बखूबी जानते होंगे कि सड़कों पर बगैर किसी ट्रैफिक सिग्नल के यात्रा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सड़कों पर जानलेवा दुर्घटना से बचने और अनुशासन को बनाए रखनें के लिए ट्रैफिक सिग्नल का होना बेहद ही जरूरी है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि आखिर दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कब और कहां लगाया गया था? अगर नहीं तो आज इस लेख के माध्यम से हम आपको इन्हीं दिलचस्प सवालों का जवाब देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल किस देश में लगाया गया था और उस समय बगैर किसी बिजली के इसे कैसे ऑपरेट किया जाता था। साथ-साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में पहला ट्रैफिक सिग्नल कब और किस राज्य में लगाया गया था। पहली हर चीज लोगों के लिए बेहद ही खास होती है और उससे भी ज्यादा खास और आनंदित होता है सालों बाद उन पहली चीजों की कहानी सुनाना। दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल आज से तकरीबन 150 सालों पहले लंदन में स्थापित किया गया था। इस ट्रैफिक सिग्नल को 09 दिसंबर, 1868 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल्कुल ठीक

सामने ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट और ब्रिज स्ट्रीट के चौराहे पर लगाया गया था। इस ट्रैफिक सिग्नल को जॉन पीक नाइट ने डिजाइन किया था। बता दें, जॉन पीक नाइट को रेलवे सिग्नल इंजीनियर का अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल उस समय सड़कों पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए किया था। यह उस समय का सबसे अनोखा सिग्नल था। जो किसी बिजली से नहीं, बल्कि गैस-लैंप से चलाया जाता था। रात के समय यात्री को निर्देश देने के लिए लाल और हरी गैस लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। बता दें, यह सिग्नल ऑटोमेटिक नहीं था, बल्कि इसे पुलिस अधिकारी द्वारा बगल में खड़े होकर मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था। इसके साथ ही उस समय के ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट नहीं हुआ करती थी। पहले के सिग्नल में केवल दो रंग थे। लाल रंग रुकने और हरा रंग सावधानी या फिर जाने का संकेत हुआ करता था। दुनिया के पहले ट्रैफिक लाइट को जिस खुशी के साथ लगाया था। उसका अंत उतना ही दुखद था। बता दें, यह ट्रैफिक सिग्नल गैस से बनाया गया था। गैस लीक होने की वजह से इसमें एक तेज व खतरनाक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण सिग्नल पर अपनी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी की मौत भी हो गई थी। इस हादसे के बाद इस ट्रैफिक सिग्नल को सड़क से हटा दिया गया और उसके बाद सड़क पर ऐसा कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाया गया था। दुनिया का गैस ट्रैफिक सिग्नल असफल होने के बाद इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल की नींव साल 1914 में रखी गई थी। यह इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल अमेरिका के राज्य क्लीवलैंड में लगाया गया था। इसके साथ ही भारत की पहली ट्रैफिक लाइट साल 1953 में चन्नई में लगाई गई थी। बता दें, चन्नई के लोगों ने इस ट्रैफिक लाइट का तकरीबन दस सालों तक इस्तेमाल किया था। इसके बाद इसे बेंगलुरु में लगाया गया और धीरे-धीरे ट्रैफिक लाइट पूरे भारत में फैल गई।

डेविस कप: दक्षिणेश्वर सुरेश बने भारत के नए नायक, गुमनामी से स्टारडम तक का सफर

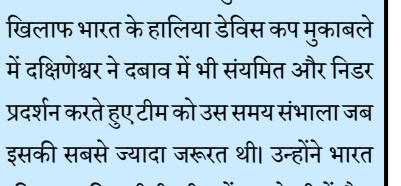

भारतीय टेनिस के नए नायक दक्षिणेश्वर सुरेश ने वर्षों के कड़े संघर्ष, अनुशासन और अमेरिकी कॉलेज टेनिस के अनुभव से डेविस कप में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जो हाशिये से मुख्यधारा तक उनके प्रेरणादायक सफर को दर्शाता है। टेनिस से उनका जुड़ाव पारिवारिक संबंधों से है। उनके पिता सुरेश एक्का डिंडीगुल के क्लब स्तर के खिलाड़ी थे। उनके इन्हीं शुरुआती संपर्कों के कारण दक्षिणेश्वर के लिए चेन्नई में लक्ष्मण चक्रवर्ती के रूप में कोच ढूंढने में मदद मिली। उन शुरुआती दिनों से ही कड़ी मेहनत जारी रही। इस दौरान 2010 और 2016 के बीच दक्षिणेश्वर चेन्नई में प्रतिदिन लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा बस से करते थे। अब उनकी यह मानसिक दृढ़ता डेविस कप के मंच पर दिखाई दे रही है। बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ भारत के हालिया डेविस कप मुकाबले में दक्षिणेश्वर ने दबाव में भी संयमित और निडर प्रदर्शन करते हुए टीम को उस समय संभाला जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने भारत की 3-2 की करीबी जीत में अपने तीनों मैच जीते। वह मई में वेक फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। चक्रवर्ती दक्षिणेश्वर को अपना सबसे अच्छा शिष्य कहते हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, ''वह मेरा सबसे अच्छा शिष्य है। वह सब कुछ व्यवस्थित रखता है। कपड़े, जूते, किट बैग। वह हमेशा चीजों को एक ही जगह पर रखता है। उसकी टोपी, रैकेट, सब कुछ हमेशा एक ही जगह पर रखा रहता है। वह बहुत ही व्यवस्थित है।

नामीबिया को हराकर नीदरलैंड्स ने T20 World Cup 2026 में दर्ज की पहली जीत

राजीव शुक्ला ने ICC को धन्यवाद दिया,

कहा- पाकिस्तान विवाद का निकला 'बहुत अच्छा समाधान

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने 'बहुत अच्छा समाधान निकाला' जिसके कारण पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार वापस ले लिया। बांग्लादेश और श्रीलंका के आग्रह के बाद पाकिस्तान सरकार ने बहिष्कार की अपील वापस लेने का फैसला किया जिसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। शुक्ला ने पत्रकारों से कहा, ''मैं बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी अध्यक्ष (जय शाह) और उसके पदाधिकारियों का बहुत अच्छा समाधान निकालने के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ चर्चा के बाद और सभी पक्षों की बात सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया है।'' उन्होंने कहा, ''यह फैसला क्रिकेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट जारी रहना चाहिए और अब विश्व कप को बड़ी सफलता मिलेगी। जहां तक आईसीसी का सवाल है तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी की प्रशंसा की है। उसने सभी पक्षों की बात सुनी और सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया।''

शुक्ला ने आगे कहा, ''आखिर में क्रिकेट सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है।'' बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख अमीनुल इस्लाम ने ढाका में बयान जारी किया था जिसमें पाकिस्तान से बहिष्कार वापस लेने की अपील की गई थी। इसके बाद यह तय हो गया था कि पाकिस्तान बहिष्कार वापस ले लेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भी फोन पर बात की, जिन्होंने उनसे टीम को मैच खेलने की अनुमति देने का आग्रह किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने आईसीसी के साथ अपनी बातचीत के बारे में शरीफ को जानकारी दी इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने बयान जारी करके अपनी टीम को यह मैच खेलने की अनुमति प्रदान की थी।

न्यूजीलैंड ने यूएई के उड़ाए परखच्चे,

15.2 ओवर में चेज कर लिया 174 रनों का टारगेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के 11वें लीग मैच में न्यूजीलैंड और यूएई की टीमें मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने थीं। यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यूएई की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए, जिसमें शराफू और कप्तान मुहम्मद वसीम ने अर्धशतक जड़ा। दोनों के बीच 175 रनों की साझेदारी हुई, जो टी20 वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी के रूप में दर्ज की गई।यूएई की ओर से यह मजबूत स्कोर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने इसे आसानी से हासिल कर दिखाया। न्यूजीलैंड को 174 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने सिर्फ 15.2 ओवर में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए फिन एलेन ने 84 रन और टिम सीफर्ट ने 89 रन बनाए। उनकी इस साझेदारी ने पूरी मैच की दिशा ही बदल दी।इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराया था। इस प्रकार टीम लगातार दोनों मैच जीतकर अपने ग्रुप में मजबूत

स्थिति में है।मैच के दौरान यूएई की बल्लेबाजी ने शुरुआत तो अच्छी दी, लेकिन न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाजों ने कम ओवरों में लक्ष्य हासिल कर टीम को आसानी से जीत दिला दी। शराफू और मुहम्मद वसीम की बड़ी साझेदारी के बावजूद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने शानदार संतुलन दिखाया।इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम टूर्नामेंट में अपनी शानदार स्थिति बनाए हुए है और अन्य मैचों में भी इसी प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं, यूएई को अपने अगले मैच में सुधार करने की आवश्यकता है, खासकर बल्लेबाजी और साझेदारी के मामले में।

इंडिया-पाकिस्तान मुकाबले पर शशि थरूर का बयान:

क्रिकेट से राजनीति को अलग रखें

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें खेलों का राजनीतिकरण पसंद नहीं है और उन्हें खुशी है कि टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के साथ क्रिकेट जारी रहेगा। शशि थरूर की यह टिप्पणी पाकिस्तान द्वारा अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ समूह चरण के विश्व कप मैच का बहिष्कार करने के फैसले से पीछे हटने के बाद आई है। उन्होंने कहा कि मैं एक राजनेता हूं, लेकिन मुझे क्रिकेट और खेलों में राजनीति पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि खेल एक अलग क्षेत्र है, एक अलग खेल है। उन्होंने कहा कि राजनेता अपनी राजनीति कहीं और करें, राजनयिक कूटनीति में अपना काम करें और क्रिकेट खिलाड़ी अपना खेल खेलें। मुझे खुशी है कि कम से कम इस मैच के साथ क्रिकेट जारी रहेगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा? यह एक अलग बात है। जाहिर है, हम अपने देश के साथ हैं।

मैच होना ही चाहिए। सोमवार को पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले निर्धारित मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीसीबी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के परिणामों की जानकारी देने के बाद लिया गया। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के समर्थन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ समूह चरण के विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया था। बांग्लादेश को आईसीसी द्वारा "सुरक्षा चिंताओं" के कारण भारत से बाहर मैच स्थल स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था।

कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए

बर्मिंघम का आसमान हो गया गुलाबी

यह रंग आसमान से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद तेज रोशनी और मौसम की वजह से बना था. लोगों ने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए. लेकिन असल वजह कोई अंतरिक्षीय घटना नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद रोशनी और मौसम का मेल था.

ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में लोगों ने देखा कि पूरा आसमान गुलाबी रंग में चमक रहा है. (Photo:X/ @@shaqxii)

बर्मिंघम में एक रात लोगों ने देखा कि आसमान गुलाबी रंग में चमक रहा है. लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि कहीं ये ऑरोरा या कोई रहस्यमयी घटना तो नहीं. ऑरोरा एक प्राकृतिक रोशनी का खेल है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) के आसमान में दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आसान और दिलचस्प थी. यह रंग आसमान से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद तेज रोशनी और मौसम की वजह से बना था. लोगों ने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए. लेकिन असल वजह कोई अंतरिक्षीय घटना नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद रोशनी और मौसम का मेल था. बर्मिंघम सिटी फुटबॉल क्लब के स्टेडियम सेंट एंड्रयूज स्टेडियम में उस रात एफए कप का मैच चल रहा था. स्टेडियम में लगी तेज गुलाबी एलईडी लाइट जल रही थीं. उसी समय भारी बर्फबारी हो रही थी, आसमान में घने और नीचे तक फैले बादल थे. इन हालात में स्टेडियम की गुलाबी रोशनी बर्फ और बादलों से टकराकर चारों ओर फैल गई. और पूरा आसमान गुलाबी दिखने लगा. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बर्फ और बादल शीशे (दर्पण) की तरह काम करते हैं.

निशाने पर गूगल की सोशल मीडिया पॉलिसी

आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल और इंटरनेट बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, वहीं उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर माता-पिता की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे समय में गूगल की एक पॉलिसी को लेकर उठे सवालों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. एक मां का आरोप है कि गूगल बच्चों को सीधे ईमेल भेजकर उन्हें माता-पिता की निगरानी से बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहा है. इस मुद्दे ने न सिर्फ पेरेंट्स को नाराज किया है.

सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

गैंडे से भिड़ गया नन्हा हिरण

इस महीने की शुरुआत में पोलैंड के एक चिड़ियाघर से एक मजेदार वीडियो सामने आया है. इसे काफी लोग शेयर कर रहे हैं.

यह वीडियो एक नन्हें हिरण और विशालकाय गैंडे की लड़ाई का है, जिसे लोग खूब शेयर कर रहे हैं और इंटरनेट पर ये जोड़ी छाया हुआ है. रॉयटर्स के मुताबिक, इस महीने पोलैंड के एक चिड़ियाघर में एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई. इसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है. जब एक छोटा सा मुंटजैक हिरण एक विशाल गैंडे से भिड़ गया. ऐसा लगा कि वह जीत गया. 'मुंटजैक डैड' नाम का 17 किलो का हिरण 1660 किलो की मारूसिया (गैंडे) को घूरते हुए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था. यह वीडियो व्रोकला चिड़ियाघर में फिल्माया गया था.

सुरक्षा और अव्यवस्था को लेकर उठे सवाल

भारतीय ने दिखाई यूरोप की असलियत

यूरोप लंबे समय से दुनियाभर के यात्रियों का ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है. फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की चमक-दमक फिल्मों और सोशल मीडिया रील्स में कुछ ऐसी दिखाई जाती है कि लोग वहां जाने का सपना संजो लेते हैं, लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने यूरोप की उस तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आमतौर पर इंटरनेट पर दिखाई जाती है. भारतीय ट्रैवल व्लॉगर प्रतीक सिंह ने अपने वायरल वीडियो में यूरोप का एक अलग ही चेहरा दिखाया है. वीडियो में कई यूरोपीय शहरों की सड़कों पर फैली गंदगी साफ नजर आती है. प्रतीक का कहना है कि सोशल मीडिया रील्स में जो यूरोप दिखाया जाता है, हकीकत उससे काफी अलग है. प्रतीक सिंह वीडियो में बताते हैं कि यूरोप घूमने के लिए शेंगेन वीजा लेना आसान नहीं है. इसके लिए छह महीने के बैंक स्टेटमेंट, तीन महीने के ITR, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और महंगे फ्लाइट टिकट्स की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद, उनके मुताबिक, वहां पहुंचने पर कई जगहों पर गंदगी, अव्यवस्था और अपराध देखने को मिलते हैं. वीडियो में वह कहते हैं कि 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके आप यूरोप यही देखने आते हैं? ये सब तो भारत में भी देखा जा सकता है. प्रतीक ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि आज के समय में जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे पूर्वी देश टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में आगे निकल चुके हैं.

व्लॉगर ने यूरोप का दिखाया नजारा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए (Photo:Insta/@travelwprateek)

सलमान खान और संजय दत्त ने किया ट्रेलर में तहलका, अपकमिंग सऊदी एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' हुई रिलीज

अपकमिंग सऊदी एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया और फिल्म प्रेमियों के बीच सनसनी मच गई है। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज सितारे सलमान खान और संजय दत्त ने कैमियो किया है। हालांकि दोनों का रोल कैमियो ही है, लेकिन ट्रेलर में उनकी उपस्थिति इतनी दमदार है कि वह पूरी फिल्म का आकर्षण बन गए हैं।ट्रेलर की शुरुआत ही हाई-एंड एक्शन और सस्पेंस से होती है। फिल्म में दिखाए गए पीछा, स्टंट और एक्शन सीन्स दर्शकों को शुरुआत से ही बांधे रखते हैं। सलमान खान की स्टाइलिश और करिश्माई एंट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, वहीं संजय दत्त की छवि और उनका ऑन-स्क्रीन डायलॉग delivery ट्रेलर में एक अलग ही ऊर्जा जोड़ते हैं। दोनों सुपरस्टार्स ने कम स्क्रीन टाइम में भी इतनी छाप छोड़ी है कि फैंस और फिल्म विश्लेषक दोनों इसे फिल्म का हाइलाइट मान रहे हैं।फिल्म की कहानी सऊदी अरब की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कथानक में एक खतरनाक अपराध और उसके पीछे छिपे रहस्य को उजागर करने का रोमांच है। निर्माताओं ने कहा है कि फिल्म में सस्पेंस, ड्रामा और हाई-ऑक्टेन एक्शन का शानदार मिश्रण है। ट्रेलर में दिखाए गए एडवेंचर और खतरे के पल दर्शकों के लिए एक थ्रिल राइड जैसा अनुभव देते हैं।निर्देशक और निर्माता ने स्पष्ट किया है कि सलमान और संजय दत्त के कैमियो के बावजूद फिल्म की कहानी अपने आप में मजबूत है। इंटरनेशनल लेवल की लोकेशंस, एक्शन sequences और तकनीकी क्वालिटी को लेकर फिल्म का बजट भी काफी बड़ा बताया जा रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि सलमान और संजय दत्त की उपस्थिति ट्रेलर की लोकप्रियता को बढ़ाने के साथ-साथ फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई में भी योगदान दे सकती है। ट्रेलर रिलीज होते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है। फैंस दोनों सितारों की धमाकेदार एंट्री और एक्शन सीन को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेलर के शेयर और व्यूज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आलोचक भी इसे एक हाई-एंड एक्शन फिल्म मान रहे हैं, जिसमें भारतीय स्टार्स की उपस्थिति इसे और ग्लोबल अपील देती है।फिल्म की रिलीज़ डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन निर्माताओं ने संकेत दिए हैं कि यह जल्द ही बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। फिल्म के रिलीज होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि सलमान और संजय दत्त के कैमियो ट्रेलर जितना ही प्रभाव फिल्म में डाल पाते हैं या नहीं।कुल मिलाकर, '7 डॉग्स' का ट्रेलर दर्शकों में उत्साह और जिज्ञासा दोनों पैदा करने में सफल रहा है। एक्शन, थ्रिल और स्टार पॉवर का जबरदस्त मिश्रण इसे इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनाता दिख रहा है।

सहारा की जमीन पर विधानसभा भवन निर्माण की तैयारी शुरू, LDA कराएगा सर्वे

लखनऊ के सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर नए विधानसभा भवन निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। LDA ने कंसल्टेंसी कंपनी से तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी कर रिपोर्ट बनाने को कहा, जिससे शासन अंतिम निर्णय लेगा।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ: सहारा शहर की विपुल खंड में स्थित जमीन पर नए विधानसभा भवन के निर्माण की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सलाहकार (कंसल्टेंट) कंपनी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस जमीन का तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए एक कंसल्टेंसी कंपनी नियुक्त की है। यह सर्वे और रिपोर्ट आगे नए विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर की रूपरेखा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।जानकारी के अनुसार, गोमतीनगर में सहारा इंडिया को करीब 245 एकड़ जमीन आवंटित थी। यह जमीन पहले नगर निगम और LDA की थी, जिसे लीज पर सहारा समूह को दिया गया था। हालांकि, जमीन के गलत उपयोग और लीज की शर्तों के उल्लंघन के आरोप सामने आने के बाद लखनऊ नगर निगम ने लीज रद्द कर दी। अब यह पूरी जमीन शासन के नियंत्रण में है। इसके बाद इस जमीन पर नए विधानसभा भवन के निर्माण की दिशा में कदम उठाए गए हैं।एलडीए ने नियुक्त कंसल्टेंसी कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह दो महीने के भीतर जमीन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। रिपोर्ट में जमीन की सटीक सीमाओं का निर्धारण, मौजूदा भौतिक स्थिति, वर्तमान उपयोग, निर्माण की संभावनाओं और चुनौतियों का विस्तृत आकलन शामिल होगा। तकनीकी और पर्यावरणीय पहलुओं का अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि 245 एकड़ जमीन पर नया विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर किस स्वरूप में विकसित किया जाएगा।अधिकारियों के मुताबिक, कंसल्टेंसी कंपनी की रिपोर्ट एलडीए के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि भवनों का लेआउट, क्षमता, सड़क और पार्किंग की व्यवस्था, हरित क्षेत्र, सुरक्षा इंतजाम और अन्य जरूरी सुविधाओं को किस प्रकार विकसित किया जाएगा।इस परियोजना के समन्वय और संचालन के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) को विशेष कार्य इकाई के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर काम किया जा सके। कंसल्टेंसी कंपनी की रिपोर्ट इन विभागों के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगी, जो आगे की योजना और डिजाइन के लिए मार्गदर्शक साबित होगी।सहारा शहर की जमीन पर यह परियोजना काफी अहम मानी जा रही है। लीज रद्द होने और जमीन के शासन के नियंत्रण में आने के बाद यह पहला महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों के मुताबिक, बिना तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी के इस बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।सहारा शहर में करीब 170 एकड़ में फैले परिसर को 6 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। इसके बाद सुब्रत कोठी और अन्य इमारतों में रखे बेशकीमती सामान को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें सुब्रत रॉय की लग्जरी कारों का बेड़ा भी शामिल है। हालांकि, उनके ऑफिस के म्यूजियम में रखे पुराने लंब्रेटा स्कूटर को फिलहाल नहीं हटाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह स्कूटर अभी वहीं रहेगा।कुल मिलाकर, सहारा शहर की जमीन पर नए विधानसभा भवन निर्माण की प्रक्रिया का यह शुरुआती चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कंसल्टेंसी कंपनी की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह परियोजना किस रूप में आगे बढ़ेगी और लखनऊ में आधुनिक प्रशासनिक केंद्र का स्वरूप कैसा होगा।

लखनऊ में बंद फ्लैट में बेहोश हुए रिटायर डिप्टी कमिश्नर

लखनऊ: पुलिस ने एक बुजुर्ग की जान बचाई। बुजुर्ग अपार्टमेंट में अपने फ्लैट पर थे। पुलिस को सूचना मिली कि वह न फोन उठा रहे हैं, न ही कुछ बोल रहे हैं। इसके बाद पुलिस आनन-फानन में पहुंची। चौथी मंजिल पर चढ़कर 2 दरवाजे तोड़े। फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि बुजुर्ग बेड पर लगभग अचेत पड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

घटना महानगर थाना क्षेत्र की सोमवार दोपहर की है। डोगरा कोठी में फ्लैट नंबर 405 पर रहने वाले 85 वर्षीय वंशीधर डोगरा फोन नहीं उठा रहे थे। उनकी मेड पहुंची लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। वह वापस लौट गई। उनका केयरटेकर पहुंचा तब भी अंदर से दरवाजा नहीं खुला। काफी देर तक संपर्क न होने और दरवाजा न खुलने से आशंका गहराई तो पुलिस बुलाई गई। बुजुर्ग वंशीधर डोगरा जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) से डिप्टी कमिश्नर पद से रिटायर हैं। पिता के बीमार होने की सूचना पर अल्मोड़ा से उनके एक बेटे लखनऊ आ रहे हैं। वहीं परिवार के लोग आगरा और दिल्ली में भी रहते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वंशीधर कोठी में अकेले ही रहते हैं। पुलिस ने बताया है कि सवेरे मेड खाना बनाने पहुंची थी। अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो वह वापस लौट आई। उसने अपार्टमेंट (कोठी) के गार्ड को सूचना दी। गार्ड ने वंशीधर के केयरटेकर शिवम को फोन किया। शिवम पहुंचा तो वह भी दरवाजा नहीं खुलवा पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर 2 दरवाजे तोड़े। उसके बाद देखा कि वंशीधर अचेत अवस्था में पड़े हैं। पुलिस उन्हें तत्काल लारी लेकर गई। वहां से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। उसके बाद बुजुर्ग के बेटे के निवेदन पर उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वहां केयरटेकर शिवम मौजूद है।

"लखनऊ: गोदाम में विस्फोटक मिलने से हड़कंप, बम स्क्वॉड ने इलाके को किया सील"

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

इटौंजा कस्बे में एक गोदाम में भारी मात्रा में विस्फोटक होने की सूचना से सोमवार देर रात हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर मौजूद रही। गोदाम में विस्फोटक मिला। जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, इटौंजा कस्बे में जुबैर ट्रेडर्स के नाम से जुबैर का गोदाम है। सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि गोदाम में बड़ी संख्या में विस्फोटक पदार्थों का भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही एडीसीपी नॉर्थ ऋषभ रुणवाल, एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर इटौंजा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गोदाम के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां न पहुंच सके। सूचना फैलते ही कस्बे और आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद गोदाम खुलवाकर बम निरोधक दस्ते की मदद से जांच शुरू की गई। एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान गोदाम में विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण भी किया गया था। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। मंगलवार को पुलिस टीम दोबारा जांच करेगी, जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर गोदाम मालिक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लोधेश्वर जल चढ़ाने जा रहे दोस्तों का लखनऊ में एक्सीडेंट

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

अयोध्या रोड पर सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो दोस्तों की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों दोस्त कानपुर से बाराबंकी स्थित प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने परिजनों को अवगत कराया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान कानपुर के रामनगर निवासी 32 वर्षीय अमित कुमार पांडेय के रूप में हुई है। अमित अपने दोस्त आमोद बाजपेई के साथ सोमवार शाम को घर से निकले थे। परिवार के अनुसार, अमित हर साल श्रद्धा और आस्था के साथ लोधेश्वर महादेव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करता था। इस बार भी वह अपने मित्र के साथ उसी उद्देश्य से यात्रा पर निकला था।देर रात अयोध्या रोड पर जीएस लोन के सामने उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की इमरजेंसी में भर्ती कराया।अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अमित कुमार पांडेय को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनके दोस्त आमोद बाजपेई की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज लोहिया संस्थान में जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अज्ञात वाहन की पहचान और तलाश की जा रही है।मृतक अमित के भाई दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार देर रात पुलिस का फोन आने पर परिवार को हादसे की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि अमित कंप्यूटर सप्लाई का काम करता था और अपने काम के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहता था। वह बिठूर विधायक अभिजीत सिंह राणा का करीबी माना जाता था। अमित की मौत की खबर मिलते ही विधायक के प्रतिनिधि भी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी।पारिवारिक जानकारी के अनुसार, अमित की शादी करीब पांच साल पहले कानपुर की एक युवती से हुई थी,

लखनऊ में शराब ठेके के खिलाफ रातभर चला धरना

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के पसिन ढकवा गांव में देसी शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों और किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ठेका हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। सोमवार रातभर धरना चला।

सोमवार दिन में शुरू हुए प्रदर्शन में हाल ही में मारे गए संतराम रावत के परिजन भी शामिल हुए। सबने दोषियों पर कार्रवाई और शराब ठेका तत्काल बंद करने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ दिनों पहले संतराम रावत की हत्या शराब ठेके के पास ही कर दी गई थी। इस घटना के बाद से पूरे गांव में भय और तनाव का माहौल है। लोगों का आरोप है कि यह शराब का ठेका अपराध और असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा शराब बिक्री के लिए निर्धारित समय का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दिन हो या रात, किसी भी समय शराब उपलब्ध रहती है। इससे बाहरी असामाजिक तत्व देर रात तक गांव में जमा रहते हैं, जिसके कारण झगड़े, विवाद और उपद्रव की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

अखिलेश यादव बोले- अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई

समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ाकर भारतीय कृषि को संकट में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि से संबंधित हर चीज विदेश से आयात की जाएगी, तो देश के किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान क्या उगाएंगे, क्या बेचेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट आने से पहले और बाद में भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने देश बचे हैं जिनसे मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाए हैं। सपा नेता ने दावा किया कि अमेरिका के साथ डील नहीं, ढील हुई है। अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों करवाया गया। उन्होंने भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 18 प्रतिशत शुल्क और अमेरिकी उत्पादों पर भारत में शून्य शुल्क का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि हमारे देश की जनता जानना चाहती है कि शून्य बड़ा है या 18? क्या भाजपा का गणित यह है कि शून्य और 18 बराबर हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सब कुछ विदेश से आएगा तो देश के किसान क्या उगाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट दिशाहीन है और इसे लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित बनेगा। अखिलेश यादव का कहना था कि इस बजट में 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान और मजदूर बजट में अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ''प्रधान संसदीय क्षेत्र'' वाराणसी में राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यादव ने दावा किया कि वाराणसी में वहां लगभग 100 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। नेपाल नरेश की ओर भेंट किया गया घंटा भी लापता है।

बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ का बयान:

कयामत तक बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा

टीवी भारतवर्ष बाराबंकी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी में आयोजित धार्मिक सभा में बाबरी मस्जिद मुद्दे पर अपने कड़े रुख को फिर दोहराया और स्पष्ट किया कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा, यहां तक कि कयामत तक भी नहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जानकी मंदिर में 10वें श्री हनुमान विराट महायज्ञ और श्री रामार्चा पूजन के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कथनी और करनी में हमेशा ईमानदार रहती है और जो कहा जाता है, वही किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राम लल्ला के लिए जो वादा किया था, वह पूरा किया। उन्होंने कहा, "हमने कहा था कि राम लल्ला, हम आएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। इसीलिए हम आज भी कह रहे हैं कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं होगा। और चूंकि वह दिन कभी नहीं आएगा, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण की उम्मीद रखने वाले लोग भ्रम में हैं और उन्हें वास्तविकता समझनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जिन्हें उन्होंने अवसरवादी कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग भगवान राम को केवल संकट के समय ही याद करते हैं और बाकी समय उन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भगवान राम पहले ही भूल चुके हैं और उनका मार्गदर्शन पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अतीत में राम भक्तों पर गोली चलाने वाले या धार्मिक कार्यों में बाधा डालने वालों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे कानून का सम्मान करें और 'कयामत के दिन' का इंतजार करने के बजाय भारत के कानूनी ढांचे के अनुसार जीवन जीने पर ध्यान दें। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि इस देश में कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "कानून का पालन करने से आपको लाभ होगा। कानून तोड़ने का रास्ता सीधे सजा की ओर ले जाता है। कानून तोड़कर जन्नत का सपना देखने वाला कोई भी व्यक्ति भ्रम में जी रहा है।" मुख्यमंत्री ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं से जुड़ा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को अयोध्या यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर पर भव्य भगवा झंडा फहराया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवा झंडा भारत के गौरव और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है और यह जनता में उत्साह और प्रेरणा बनाए रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता में आस्था और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या में हुए राम मंदिर निर्माण के कार्यों की समीक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम लल्ला के मंदिर के निर्माण से न केवल धार्मिक आस्था को बल मिला है, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था के पालन की भावना को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने बाराबंकी के लोगों से अपील की कि वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कर्तव्यों के साथ-साथ कानूनी कर्तव्यों का पालन भी करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद पर राजनीति करने वाले लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शासन में किसी भी तरह के विवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और कानून के अनुसार ही सभी मामलों को हल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि

अवसरवादी लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनता को वास्तविकता को समझना होगा और ऐसे लोगों की नीतियों में न फंसना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बाराबंकी में उपस्थित लोगों से अपील की कि वे भगवान राम के आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन में नैतिकता, कानून और संस्कृति का पालन करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और कानून का पालन दोनों ही समाज की प्रगति और स्थिरता के लिए जरूरी हैं। इस सभा में योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के नागरिकों और धार्मिक नेताओं को भरोसा दिलाया कि उनके शासन में कानून और धर्म का संतुलन हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अतीत में राम भक्तों के साथ जो अन्याय हुआ, उसकी याद से समाज सीख ले और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर किसी प्रकार का पुनर्निर्माण नहीं होगा और यह निर्णय कयामत तक वैध रहेगा।

योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से गहरी प्रतिक्रिया पैदा की है। उनका यह स्पष्ट रुख यह दर्शाता है कि राज्य सरकार विवादास्पद धार्मिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण में अडिग है और कानून और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दे रही है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी में दिया गया यह बयान न केवल बाबरी मस्जिद विवाद पर उनके दृष्टिकोण को दोहराता है, बल्कि कानून, धर्म और संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखने के उनके संदेश को भी स्पष्ट करता है। उन्होंने अपने भाषण में राम मंदिर आंदोलन, भगवा झंडे और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र कर जनता में धार्मिक आस्था और कानूनी चेतना दोनों को मजबूत किया।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पिकअप की टक्कर, युवक की मौत

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय रिंकू पुत्र बृजलाल, निवासी ताला सराय गांव, थाना हसनगंज, उन्नाव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, रिंकू बाइक से सहपुर तोंदा की ओर जा रहा था। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन के पास पहुंचने पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रिंकू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मृतक रिंकू खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में पत्नी अंजू और एक छोटी बेटी खुशबू हैं। परिजनों ने बताया कि रिंकू सुबह किसी काम से घर से निकला था। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। पुलिस के अनुसार, एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिकअप वाहन की पहचान कर चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ठाकुर हूं, ऐसी-तैसी कर दूंगी बैंककर्मी ने कहा: बदतमीजी से गुस्सा आया, ठाकुर होने पर गर्व

टीवी भारतवर्ष कानपुर

HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी, आस्था सिंह, जिनके 'ठाकुर हूं, ऐसी-तैसी कर दूंगी' वाले बयान का वीडियो वायरल हुआ था, ने सामने आकर मामले की सफाई दी है। आस्था ने वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी ग्राहक के साथ अभद्रता नहीं की। उनका विवाद बैंक की एक महिला संविदा कर्मचारी के पति से हुआ था। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी के पति ने उनकी जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया, जिससे गुस्सा आया। आस्था ने कहा कि वे अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ठाकुर होने पर गर्व है।आस्था का वीडियो पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें गालियां देते और गुस्से में लैपटॉप उठाकर किसी पर हमला करने का प्रयास करते देखा जा सकता है। हालांकि, यह वीडियो 6 जनवरी का बताया गया है। आस्था पनकी की HDFC ब्रांच में तैनात हैं। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इसे गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है।बताया गया है कि महिला कर्मचारी ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था और रिलीविंग की मांग की थी। इस दौरान महिला कर्मचारी की ननद सुबह से ही ब्रांच में मौजूद थी, जिससे हल्की बहस हो गई। बाद में महिला कर्मचारी ने यह मामला अपने पति को बताया। महिला कर्मचारी का पति वर्किंग आवर के खत्म होने के बाद बैंक आया और आस्था सिंह के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।आस्था सिंह ने कहा, "महिला कर्मचारी के पति ने मेरी डेस्क पर आकर मेरी जाति पूछी और धमकी भरे शब्द कहे। मैं मानती हूं कि मेरे कुछ शब्द गलत हो सकते हैं। सार्वजनिक सेवा में शब्दों का चयन सोच-समझकर होना चाहिए, लेकिन धमकी और अपमानजनक भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को जातिवाद का मुद्दा बनाकर पेश किया गया है, जो सही नहीं है। मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं ठाकुर हूं और मुझे गर्व है। जय श्रीराम।"आस्था ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस केस में उन्होंने इंटरनल मेल अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर दिया है और सबको पता है कि वे गलत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो वे मानहानि का केस करने की भी तैयारी कर रही हैं।वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आस्था को भयंकर धमकियां भी मिल रही हैं, जिनमें रेप की धमकी और बाल काटने जैसी बातें शामिल हैं। आस्था ने कहा कि हर इंसान फेमस होना चाहता है, लेकिन वह गलत तरीके से फेमस नहीं होना चाहतीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गलत मायने में फेमस किया जा रहा है।इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया और मीडिया जगत में विवाद को और बढ़ा दिया है। आस्था सिंह का बयान और उनका वीडियो वायरल होना यह दर्शाता है कि पेशेवर माहौल में व्यक्तिगत विवाद और सोशल मीडिया की भूमिका कितनी संवेदनशील हो सकती है।

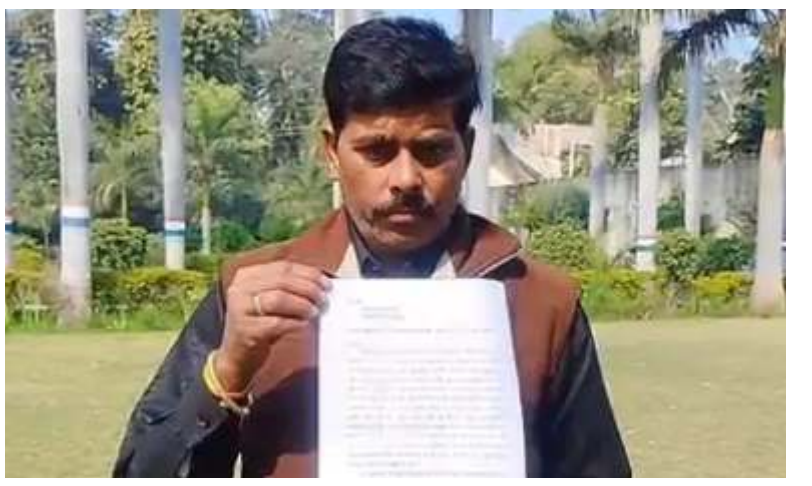

"पीएम आवास योजना में फर्जी रिपोर्ट का आरोप: उन्नाव मजदूर ने CM से न्याय की मांगी मदद"

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के पुरवा विकास खंड के ग्राम भदनोग के निवासी मजदूर अजय कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। अजय का आरोप है कि उनके मकान की वास्तविक स्थिति को लेकर गलत रिपोर्ट तैयार की गई, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी ने उनके कच्चे मकान को पक्का मकान दिखाते हुए फर्जी रिपोर्ट तैयार की, जिसके कारण उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।अजय कुमार तिवारी, जो कि देशराज तिवारी के पुत्र हैं, ने बताया कि वह कई साल पहले अपने पिता और बड़े भाई से अलग हो गए थे। उनके पास अपनी जमीन नहीं है और वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अजय के तीन छोटे बच्चे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसी वजह से वह अब तक अपना पक्का मकान नहीं बना पाए।आवास की कमी और बेहतर जीवन की उम्मीद में अजय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया। लेकिन उनके अनुसार, ग्राम विकास अधिकारी ने सही रिपोर्ट देने के बदले उनसे अवैध शुल्क की मांग की। जब अजय यह पैसा देने में असमर्थ रहे, तो अधिकारियों ने उनके पिता के मकान को उनका मकान मानकर रिपोर्ट तैयार कर दी। अजय ने स्पष्ट किया कि वह वर्षों से अपने पिता से अलग रह रहे हैं, उनका अलग राशन कार्ड और परिवार है, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई।अजय का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया उन्हें योजना से वंचित करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई।

उन्होंने कहा कि इस अनियमितता के कारण उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो गई है। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित और पक्का मकान पाने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन अधिकारी की गैरजिम्मेदार कार्रवाई ने उनके सपने को बाधित कर दिया।अजय कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा कि वह अत्यंत मायूस हैं और अब उन्हें न्याय की अंतिम उम्मीद शासन से ही है। उन्होंने मांग की है कि उनकी आवास योजना की वास्तविक और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने दोषी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है।अजय के पत्र में यह भी उल्लेख है कि इस तरह की अनियमितताएं न केवल आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने से रोकती हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि अगर सही और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो गरीब और असहाय लोगों के अधिकार लगातार प्रभावित होते रहेंगे।स्थानीय लोग भी अजय की इस शिकायत से चिंतित हैं और उनका कहना है कि अगर प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ तो ऐसी घटनाएं आम होती जाएंगी। अजय का कहना है कि उनका मकान और परिवार का जीवन सुरक्षित होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें न्याय मिलने की सख्त जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए।इस मामले में अब नजर मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों की तरफ है कि वे इस गंभीर आरोप की जांच कर निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, ताकि अजय कुमार तिवारी और उनके परिवार को उनका कानूनी हक मिल सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्नाव में ट्रक की टक्कर से किशोर की मौत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

पुरवा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसे में 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। किशोर अपने जीजा के साथ बाइक से बाजार जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक किशोर की पहचान प्रिंस (12) के रूप में हुई है, जो मोहनलालगंज तहसील के निगोहां थाना क्षेत्र का निवासी था। वह अपने जीजा के साथ बाइक पर पुरवा क्षेत्र की ओर जा रहा था। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के गंदे नाले के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान प्रिंस की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। परिजन प्रिंस को कानपुर से लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। प्रिंस अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर से परिवार में शोक छा गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुरवा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। प्रिंस के जीजा का इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

पल्लवी को बाल पकड़कर पुलिस ने गाड़ी में बैठाया, विधानसभा कूच के दौरान झड़प

लखनऊ में पल्लवी पटेल ने UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में मार्च निकाला। विधानसभा कूच के दौरान पुलिस ने उन्हें और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पल्लवी ने विरोध करते हुए सड़क पर लेटकर धरना दिया। अंततः पुलिस ने उन्हें बाल पकड़कर गाड़ी में बैठाया। उन्होंने आरक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज जारी रखी।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में आज पल्लवी पटेल और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। पल्लवी पटेल UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल रही थीं। इस मार्च में विशेष रूप से महिलाएं शामिल थीं और उन्होंने IT चौराहा से होते हुए विधानसभा तक जाना था। मार्च का उद्देश्य आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना और नए UGC नियमों के समर्थन में जनसंपर्क करना था।जब मार्च रिजर्व पुलिस लाइन के पास पहुंचा, तो पुलिस ने पल्लवी पटेल को रोक दिया। पुलिस ने मार्च मार्ग पर बड़ी-बड़ी कंटीली बैरिकेडिंग लगा दी थी। पल्लवी ने बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान पुलिस और पल्लवी पटेल के बीच झड़प शुरू हो गई। झड़प के दौरान पल्लवी सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और आंदोलनकारी उनके साथ रुक गए।पुलिस ने कई मिनट तक पल्लवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से हटने को तैयार नहीं थीं। करीब 15 मिनट तक मान-मनौव्वल के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। पुलिस ने एक-एक कर सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें गाड़ियों में बैठाया। हालांकि, पल्लवी पटेल सड़क पर ही लेटी रहीं और गाड़ी तक जाने में विरोध करती रहीं।पुलिस ने कई बार कोशिश की कि पल्लवी गाड़ी में बैठ जाएं। महिला पुलिसकर्मी ने उनका हाथ और पीठ पकड़कर उन्हें अंदर करने का प्रयास किया, लेकिन पल्लवी ने विरोध जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बाल पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। इस कार्रवाई के बाद सभी कार्यकर्ताओं और पल्लवी को हिरासत में ले जाया गया।पल्लवी पटेल ने इस दौरान कहा कि UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को टालना आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, बल्कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के न्याय और अधिकारों का सवाल है। पल्लवी ने कहा कि इस नियम के विरोध में आवाज उठाना उनका कर्तव्य है और वे इसे राजनीतिक रूप से भी सही मानती हैं।पल्लवी पटेल अपना दल (कमेरावादी) की अध्यक्ष हैं और वर्तमान में उनका सपा के साथ गठबंधन है। वह कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं और लंबे समय से सामाजिक न्याय और आरक्षित वर्गों के अधिकारों के लिए सक्रिय रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं और वंचित वर्गों के मुद्दों पर आवाज उठाना केवल उनका राजनीतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि समाजिक जिम्मेदारी भी है।इस घटना ने विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में काफी हलचल मचा दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और बैरिकेडिंग के कारण मार्च का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पुलिस ने बताया कि कार्यकर्ताओं और पल्लवी की हिरासत का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना था और किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना स्थिति को नियंत्रित करना था।इस मामले की चर्चा सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी जोर-शोर से हो रही है। पल्लवी के समर्थक इसे महिला नेताओं और वंचित वर्गों के अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी हिरासत कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई।वहीं पल्लवी ने कहा कि इस मार्च और विरोध के जरिए वह UGC के नए रेगुलेशन के समर्थन में जनता और विधायकों को जागरूक करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में समानता और आरक्षित वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। पल्लवी ने यह भी जोर दिया कि इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाकर देखा जाना चाहिए क्योंकि यह पूरे समाज और शिक्षा प्रणाली के न्याय से जुड़ा हुआ है।इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि विधानसभा और आसपास के इलाके में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक आंदोलनों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। पल्लवी के विरोध और पुलिस की कार्रवाई के बीच हुई झड़प ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा को और तेज कर दिया है।

प्रयागराज के हॉस्टल में 17 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्युष राय की मौत, फर्श पर लाश मिलने से हड़कंप

टीवी भारतवर्ष प्रयागराज

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 17 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्युष राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रत्युष गाजीपुर का रहने वाला था। वह मंगलवार सुबह अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छात्रावास के कमरे में जमीन पर पड़ा मिला। उसे तत्काल बेली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। प्रत्युष पिछले चार सालों से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छात्रावास में रहकर वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले रहा था। वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था और अपने कोच और साथियों के बीच लोकप्रिय था। मंगलवार सुबह पांच बजे कुछ जूनियर जब प्रत्युष को जगाने गए तो वह फर्श पर पड़ा मिला। सोमवार रात करीब नौ बजे प्रत्युष ने अन्य खिलाड़ियों के साथ मेस में भोजन किया था। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया था। बीते कुछ दिनों से उसका रूम पार्टनर ऋषभ अपने गांव गया हुआ था, जिस वजह से प्रत्युष कमरे में अकेला रह रहा था। सूचना मिलते ही कर्नलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर में रहने वाले परिजन प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। कर्नलगंज थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।

"मथुरा: तलाक के विवाद में पति ने पत्नी पर किया हिंसक हमला, सिर पर पत्थर मारा"

टीवी भारतवर्ष मथुरा

मथुरा के कचहरी इलाके में उसे समय हंगामा हो गया जब एक पति ने सरेआम अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला थाना सदर बाजारा इलाके के सिविल लाइन्स इलाके का है। महिला तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंची तो पति ने पत्थर मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। महिला का सिर फूट गया है। जानकारी के अनुसार, मगोर्रा क्षेत्र के रहने वाले सुनील कुमार का अपनी पत्नी निधि के साथ 2 साल से तलाक का विवाद चल रहा है। इसी के चलते दोनों कोर्ट में पेशी के लिए सोमवार को आए थे। कोर्ट कार्यवाही होने के बाद दोनों बाहर निकल कर फुटपाथ पर बैठ गए और बातचीत होने लगी। इसी बीच पति-पत्नी में बहस शुरू हो गई। आरोप है कि सुनील ने निधि को धक्का देकर गिरा दिया और लात-घूंसो से मारपीट करने लगा। हद तब पार हो गई ज़ब पति ने पास ही पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठाकर पत्नी को मारना शुरू कर दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निधि दर्द से चीखती रही और सुनील उसे फुटपाथ पर गिराकर मारता रहा। शोर सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने निधि को बचाया। आरोपी पत्नी को छोड़कर मोके से भाग निकला। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनील और निधि की शादी साल 2014 में हुई थी। उनके दो बच्चे 10 वर्षीय बेटा यश और 7 वर्षीय बेटी हर्षिता हैं। बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर सुनील की तलाश कर रही है।

विधानसभा में दो विधायकों के मोबाइल जब्त, फोन बजने पर भड़के स्पीकर

यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में स्पीकर सतीश महाना दो विधायकों पर भड़क गए। घटना उस समय हुई जब सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और इसी दौरान दोनों विधायकों के मोबाइल बजने लगे। स्पीकर ने तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर कहा कि इन दोनों विधायकों के मोबाइल जब्त किए जाएँ। बताया जा रहा है कि मोबाइल बजने वाले विधायक बीजेपी के फतेहपुर सीकरी के चौधरी बाबूलाल और एक अन्य विधायक थे। स्पीकर ने सिक्योरिटी को इशारा करते हुए कहा, "दोनों माननीय सदस्यों से टेलीफोन ले लो... वे जो पीछे टोपी वाले बैठे हैं।"इस दिन विधानसभा में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा पहुंचे और उन्होंने मृतक विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी दिवंगत विधायकों को याद किया।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने बारी-बारी से दिवंगत विधायकों को सम्मानित किया। इसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि समारोह के पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।सूत्रों के अनुसार, इस दिन विधानसभा सत्र करीब 35 मिनट तक चला। सदन में मोबाइल बजने की घटना से एक बार फिर यह बात सामने आई कि सदन में गंभीर माहौल बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा और सभी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेष अवसरों पर मोबाइल का उपयोग न किया जाए।इसके अलावा, आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई कि कल, 11 फरवरी, को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे।